कीमत 5 रूपया

http://www.cgpi.org

आने वाले इंक़लाबी तूफ़ानों के लिये तैयारी करें!

मज़दूर एकता लहर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अख़बार

ग्रंथ–36, अंक – 22 | नवंबर 16–30, 2022 | पाक्षिक अख़बार | कुल पृष्ठ–8

वर्तमान स्थिति और आगे का रास्ता

हिन्दोस्तान के वर्तमान हालात गहराते आर्थिक संकट को दर्शाते हैं। जिसकी वजह से बेरोज़गारी ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच चुकी है। वेतन से प्राप्त होने वाली आय में भारी गिरावट आई है। भोजन, ईंधन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की क़ीमतें आसमान छू रही हैं। उत्पादक गतिविधियों में गतिहीनता और गिरावट के बावजूद, पूंजीवादी अरबपतियों के मुनाफ़े तेज़ी से बढ़ रहे हैं।

मज़दूरों, किसानों, महिलाओं और नौजवानों के व्यापक एकजुट विरोध के बावजूद, शासक वर्ग अपने शासन को बनाए रखने के लिए सांप्रदायिक हथकंडे, कड़े क़ानून, बड़े पैमाने पर दुष्प्रचार और पैशाचिक भटकावादी तरीकों का इस्तेमाल कर रहा है।

जैसा कि इस साल फरवरी में पंजाब में देखा गया था, पूंजीपति वर्ग शोषित लोगों की एकता को तोड़ने के लिए बहुपार्टीवादी चुनावों का इस्तेमाल अपने प्रमुख हथियार बतौर कर रहा है। लोगों को धोखा देने और उन्हें इस या उस पार्टी के पीछे लामबंध करके सांप्रदायिक लड़ाइयों में भटकाने के लिए चुनावों का इस्तेमाल किया जाता है। यह भ्रम पैदा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है कि इस संकटग्रस्त पूंजीवादी व्यवस्था के भीतर ही कोई समाधान खोजा जा सकता है।

2024 में होने वाले अगले लोकसभा चुनाव में लगभग 20 महीने बचे हैं। इस दौरान कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें हिमाचल प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना शामिल हैं। पूंजीवादी हमले के ख़िलाफ़ मज़दूरों और किसानों की एकजुट लड़ाई को कमज़ोर करने के लिए सत्ताधारी पूंजीपति वर्ग इन चुनावों का इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है।

पूंजीपतियों द्वारा नियंत्रित समाचार मीडिया भाजपा और उसके नेता नरेंद्र मोदी का प्रचार सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन टीम के रूप में कर रहा है, जो हिन्दोस्तान को तथाकथित महान ऊंचाइयों तक ले जाएगा। साथ ही शासक वर्ग भाजपा के तथाकथित विकल्पों को भी बढ़ावा दे रहा है। एक तथाकथित विकल्प कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन है, जिसका नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं। दूसरा विकल्प आम आदमी पार्टी है जिसका नेतृत्व अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं।

जैसा कि इस साल फरवरी में पंजाब में देखा गया था, पूंजीपति वर्ग शोषित लोगों की एकता को तोड़ने के लिए बहुपार्टीवादी चुनावों का इस्तेमाल अपने प्रमुख हथियार बतौर कर रहा है। लोगों को धोखा देने और उन्हें इस या उस पार्टी के पीछे लामबंध करके सांप्रदायिक लड़ाइयों में भटकाने के लिए चुनावों का इस्तेमाल किया जाता है। यह भ्रम पैदा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है कि इस संकटग्रस्त पूंजीवादी व्यवस्था के भीतर ही कोई समाधान खोजा जा सकता है।

भाजपा और जनता को फुसलाने की उसकी कला

भाजपा ने जनता को फुसलाने की कला को बहुत अच्छे से सीख लिया है, इस कला से वह सच को बदलकर लोगों के दिमाग में भर देती है और उन्हें आसानी से भटका देती है। प्रधानमंत्री मोदी का दावा है कि हिन्दोस्तानी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी स्थिति में है, जबकि सच्चाई यह है कि हाल के वर्षों में करोड़ों मज़दूर और किसान पहले से भी ज्यादा ग़रीब हो गए हैं। उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया दृष्टकोण कि 2047 तक हिन्दोस्तान एशिया की एक प्रमुख शक्ति होगा, यह टाटा, अंबानी, बिड़ला, अडानी और अन्य इजारेदार घरानों के साम्राज्यवादी उद्देश्यों को दर्शाता है।

सबका साथ सबका विकास का वादा अमीर और ग़रीब के बीच की खाई को और भी गहरा करने के वास्तविक परिणाम से बिल्कुल उलट है।

एक आत्मनिर्भर हिन्दोस्तान बनाने का बुलावा, विदेशी पूंजी पर बढ़ती निर्भरता की वास्तविकता के सामने एकदम खोखला दिखता है। विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए सभी दरवाज़े खोल दिये गये हैं। हिन्दोस्तानी इजारेदार समूहों ने सभी बाज़ारों पर संयुक्त रूप से हावी होने के लिए अमेजान, वालमार्ट, फेसबुक, माइक्रोसाफ्ट, कारगिल और अन्य विदेशी कंपनियों के साथ सांठ–गांठ कर ली है। वे हिन्दोस्तान की भूमि और श्रम दोनों के शोषण और लूट को बढ़ा रहे हैं।

शेष पृष्ठ 2 पर

सिखों के जनसंहार की 38वीं बरसी पर जनसभा :

राज्य द्वारा आयोजित सांप्रदायिक हिंसा और आतंक के ख़िलाफ़ संघर्ष जारी है!

1 नवंबर, दिल्ली और देश के अन्य भागों में आयोजित सिखों के जनसंहार की 38वीं बरसी का दिन है। उस दिन पर, राज्य द्वारा आयोजित सांप्रदायिक जनसंहार के ख़िलाफ़ संघर्ष करने वाले संगठनों ने कई विरोध प्रदर्शन किये।

राजधानी नई दिल्ली में, उस दिन जंतर–मंतर पर एक संयुक्त विरोध सभा का आयोजन किया गया। सभा स्थल पर लगे मुख्य बैनर पर इस प्रकार के नारे लिखे थे, "राज्य द्वारा आयोजित सांप्रदायिक हिंसा और आतंक के ख़िलाफ़ संघर्ष जारी है!", "एक पर हमला सब पर हमला!"

लोक राज संगठन, हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी, वेलफेयर पार्टी आफ इंडिया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माले) न्यू प्रोलतेरियन, लोक पक्ष, द सिख फोरम, जमात–ए–इस्लामी हिंद, सिटिज़न्स फॉर डेमोक्रेसी, पुरोगामी महिला संगठन, जन संघर्ष समन्वय समिति, अखिल भारतीय मुस्लिम मजलिस–ए–मुशावरत, हिंद नौजवान एकता सभा और मज़दूर एकता कमेटी द्वारा संयुक्त रूप से इस सभा का आयोजन किया गया था। सभा में राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, महिला अधिकार कार्यकर्ताओं, ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं, वकीलों, मीडिया कर्मियों, मज़दूरों, युवाओं और महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया।

"राज्य द्वारा आयोजित सांप्रदायिक हिंसा और राजकीय आतंकवाद मुर्दाबाद!", "1984 के सिख जनसंहार के आयोजकों को सज़ा दो!", "1984, 1992, 2002 और अन्य जनसंहार के आयोजकों को सज़ा दो!", "एक पर हमला सब पर हमला!" – जैसे नारे वाले बैनरों से सभा स्थल को सजाया गया था। सभा में शामिल कई लोगों के हाथों में प्लेकार्ड थे जिन पर भी इसी प्रकार के नारे लिखे थे।

लोक राज संगठन के अध्यक्ष एस. राघवन ने सभा में हिस्सा ले रहे सभी लोगों का स्वागत किया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि बैठक में भाग लेने वाले सभी संगठनों ने लगातार एकजुट होकर राज्य द्वारा आयोजित सांप्रदायिक हिंसा और राजकीय आतंक को खत्म करने और गुनहगारों को सज़ा दिलवाने के लिए अपना संघर्ष जारी रखा है। उन्होंने कहा कि 1984 में हुये सिखों के जनसंहार को

शेष पृष्ठ 3 पर

अंदर पढ़ें

- अक्तूबर क्रांति का मार्ग मजदूर वर्ग की मुक्ति का मार्ग है 2
- राज्य की आपराधिक लापरवाही 3
- ओपेक द्वारा तेल उत्पादन में कटौती से अमरीका बौखलाया 4
- पाठकों की प्रतिक्रिया 4
- नौकरियों के विनाश का कारण पूंजीवादी लालच है 5
- नोटबंदी की छठी वर्षगांठ पर 5
- मोटरगाड़ी मज़दूरों का संघर्ष 6
- किसानों का संघर्ष जारी है 7

महान अक्तूबर समाजवादी क्रांति का मार्ग ही मज़दूर वर्ग की मुक्ति का मार्ग है

105 साल पहले 7 नवंबर, 1917 को बोल्शेविक पार्टी के नेतृत्व में रूस के मज़दूरों ने क्रांति में जीत हासिल की थी और पूंजीपतियों व जमींदारों के शासन के स्थान पर अपना शासन स्थापित किया था। उस क्रांति ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। उसने दुनियाभर के सरमायदारों के दिलों में दहशत फैला दी थी। उसने सभी देशों के मज़दूरों और उत्पीड़ित लोगों में यह उम्मीद जगाई थी कि हर प्रकार के शोषण–दमन से मुक्त समाज का निर्माण करना मुमकिन है।

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केंद्रीय समिति ने अक्तूबर क्रांति के शताब्दी वर्ष में, पूरी पार्टी को इस विषय पर शिक्षित करने के लिए एक अभियान

चलाया था, कि कैसे बोल्शेविक पार्टी ने रूस के मज़दूर वर्ग को क्रांति में जीत हासिल करने के लिए नेतृत्व दिया था। उस अभियान का समापन महान अक्तूबर समाजवादी क्रांति की शताब्दी पर एक सार्वजनिक उत्सव के साथ हुआ था, जिसमें कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के महासचिव कॉमरेड लाल सिंह द्वारा मुख्य भाषण दिया गया था।

हम अपने सभी पाठकों से, कॉमरेड लाल सिंह के मुख्य भाषण और अक्तूबर क्रांति के शताब्दी वर्ष के दौरान मज़दूर एकता लहर में प्रकाशित अक्तूबर क्रांति पर लेखों का अध्ययन करने, का आह्वान करते हैं।

इनके लिंक नीचे दिए गए हैं।

वेबसाइट में लेख को पढ़ने के लिये http://www.hindi.cgpi.org/NNNN पर जायें जहां NNNN की जगह ऊपर दिया नंबर डालें।

- महान अक्तूबर क्रांति की सीख अमर रहे! हिन्दोस्तानी क्रांति की जीत के लिये हालतें तैयार करें! 4 नवम्बर, 2017 को अक्तूबर क्रांति की शताब्दी के अवसर पर, हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट गदर पार्टी द्वारा आयोजित दो–दिवसीय सम्मलेन में पार्टी के महासचिव कामरेड लाल सिंह द्वारा दिया गया मुख्य भाषण (6268)
- रूस की फरवरी क्रान्ति के अमूल्य सबक (5445)
- लेनिन के 'दूर देश से पत्र' के कुछ अंश (5444)
- लेनिन की अप्रैल थीसिस के बहुमूल्य सबक (5653)
- क्रांति और बोल्शेविकों के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ जनरल कार्निलोव के विद्रोह को कुचल दिया गया (5897)
- रूस के मजदूर वर्ग ने सरमायदारी राज का तख्ता पलट किया और खुद अपना राज बसाया (6097)
- अक्तूबर क्रांति की जीत से मजदूरों–किसानों का राज्य स्थापित हुआ (6159)

वर्तमान स्थिति और ...

पृष्ठ 1 का शेष

प्रधानमंत्री मोदी का बुलावा है कि सभी को "एकता और भाइचारे" की रक्षा की शपथ लेनी चाहिए। परन्तु राज्य द्वारा आयोजित बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा तथा मुसलमानों सहित राज्य की मनमानी का विरोध करने वालों की बढ़ती गिरफ्तारियां प्रधानमंत्री की कथनी और करनी के बीच अंतर की खाई को दर्शाती है।

कांग्रेस और "भारत जोड़ो" का अभियान

हाल के दशकों में शासक वर्ग कांग्रेस पार्टी को लगातार कमज़ोर करता आ रहा है। शासक वर्ग ने ही बदला लेने वाली पार्टी भाजपा को ताक़तवर बनाया है। कांग्रेस पार्टी को फिर से आगे लाने के लिए के लिए अब एक नई योजना शुरू की गई है। राहुल गांधी और उनकी टीम ने भारत जोड़ो का बुलावा देते हुए, कन्याकुमारी से कश्मीर तक का एक लंबा मार्च निकाल रहे हैं।

टाटा, बिड़ला, अंबानी और अन्य इजारेदार घरानों की सबसे पुरानी और भरोसेमंद कांग्रेस पार्टी अब खुद को दलित और शोषित जनता के रक्षक के रूप में दिखाने की कोशिश कर रही है। यह बेरोज़गारी, मुद्रास्फीति और किसानों की आत्महत्याओं के साथ पूंजीवाद की सभी बुराइयों के लिए भाजपा को दोषी ठहरा रही है। यह उम्मीद की जा रही है कि हिन्दोस्तान की एकता और अखंडता की रक्षा के नाम पर, अति–अमीरों को समृद्ध करने और सांप्रदायिक हिंसा और राजकीय आतंकवाद को बढ़ावा देने के कांग्रेस पार्टी के लंबे इतिहास को लोग भूल जाएंगे।

आम आदमी पार्टी

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर का इस्तेमाल हिन्दोस्तान को "दुनिया में अव्वल नंबर का देश" बनाने के अपने उद्देश्य को आगे रखने के लिये किया। उन्होंने अपनी पार्टी के भ्रष्टाचार–विरोधी तथा सुशासन इर्द–गिर्द "जनता का गठबंधन" बनाने का बुलावा दिया।

आम आदमी पार्टी का दावा है कि वह सभी के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और नौकरी तथा किसानों के लिए आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। यह इस तथ्य को छिपा रहा है कि पूंजीवाद का तख़्ता पलट किये बिना, इन वादों को पूरा करना संभव नहीं है।

कांग्रेस पार्टी यह उम्मीद कर रही है कि हिन्दोस्तान की एकता और अखंडता की रक्षा के नाम पर, अति–अमीरों को समृद्ध करने और सांप्रदायिक हिंसा और राजकीय आतंकवाद को बढ़ावा देने के कांग्रेस पार्टी के लंबे इतिहास को लोग भूल जाएंगे।

.....

आम आदमी पार्टी का दावा है कि वह सभी के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और नौकरी तथा किसानों के लिए आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। यह इस तथ्य को छिपा रहा है कि पूंजीवाद का तख़्ता पलट किये बिना, इन वादों को पूरा करना संभव नहीं है।

वही पूंजीवादी कार्यक्रम

विपक्ष की उन पार्टियों के पास भी वास्तव में कोई अलग कार्यक्रम नहीं हैं जिन्हें मीडिया में बढ़ावा दिया जा रहा है। उनके कार्यक्रमों का वर्ग चरित्र अलग नहीं है। ये सभी पार्टियां, सभी मेहनतकश लोगों की आजीविका और अधिकारों की बली चढ़ाकर, पूंजीवादी व्यवस्था की रक्षा करने और पूंजीपति वर्ग के साम्राज्यवादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के प्रति वचनबद्ध हैं। इनमें से अगर कोई भी पार्टी 2024 में सरकार बनाएगी तब भी बेहद अमीर और अमीर होंगे और ग़रीब और ग़रीब होंगे।

यह विचार कि मौजूदा संसदीय प्रणाली में चुनाव के नतीजे लोग तय करते हैं, यह एक भ्रम है। वास्तव में शासक पूंजीपति वर्ग ही यह तय करता है कि किसी एक वक़्त पर सरकार बनाने का काम उसकी कौन–सी पार्टी को सौंपा जाना चाहिए।

चुनावों के परिणामों को अपनी इच्छा के अनुसार निर्धारित करने के लिए इजारेदार पूंजीपति अपने नियंत्रण वाली विशाल धन शक्ति का तथा टीवी व सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। पैसे और मीडिया की ताक़त के अलावा, वे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में धांधली करके वोटों की गिनती में पूरी तरह से हेराफेरी का सहारा भी लेते हैं।

आगे का रास्ता

हाल के समय देश में सबसे सकारात्मक विकास यह है कि भूमंडलीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के पूंजीवादी कार्यक्रम के ख़िलाफ़ मज़दूरों और किसानों की एकता बढ़ी है। पूंजीवादी पार्टियों के बीच चुनावी होड़ से भटके बिना, इस एकता की रक्षा करना तथा उसे और मजबूत करना ही आगे का रास्ता है।

जिस तरह पूंजीपति वर्ग के शासन में केवल एक ही कार्यक्रम संभव होता है, उसी तरह मज़दूर वर्ग और लोगों को हर तरह के शोषण और दमन से मुक्त करने का भी एक ही कार्यक्रम हो सकता है। वह कार्यक्रम है पूंजीपति वर्ग के शासन को ख़त्म करना होगा और अर्थव्यवस्था की पूंजीवादी दिशा को भी ख़त्म करना।

मौजूदा संसदीय व्यवस्था इजारेदार घरानों के नेतृत्व वाले पूंजीपतियों के हाथों में निर्णय लेने की शक्ति को बनाये रखती है। इसकी जगह पर एक नई व्यवस्था को स्थापित करना होगा जिसमें निर्णय लेने की शक्ति मज़दूर वर्ग के नेतृत्व में मेहनतकश बहुसंख्यक लोगों के हाथों में हो। पूंजीवादी अरबपतियों को और भी अमीर बनाने की दिशा में काम करने के बजाय अर्थव्यवस्था को सभी मेहनतकश लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने की दिशा में उन्मुख करना होगा।

इस क्रांतिकारी कार्यक्रम के इर्द–गिर्द एकजुट होने से मज़दूर वर्ग को उनके द्वारा रोका जा रहा है, जो खुद को कम्युनिस्ट कहते हैं, लेकिन खुद एक या दूसरे तथाकथित बुर्जुआ विकल्प के पीछे भाग रहे हैं। ऐसी पार्टियां यह भ्रम फैला रही हैं कि लोग इस व्यवस्था में चुनाव के परिणाम को निर्धारित करते हैं और वे दावा कर रहे हैं कि भाजपा को हराना तत्कालिक काम है। वे यह भ्रम फैला रहे हैं कि पूंजीवाद में भी मज़दूरों और किसानों के हित में काम किया जा सकता है।

मौजूदा हालात इस भ्रम को फैलाने वाले विचारों के ख़िलाफ़ एक ठोस व संयुक्त संघर्ष करने का बुलावा सभी कम्युनिस्टों को दे रहे हैं। आगे का रास्ता मज़दूरों और किसानों के शासन को स्थापित करने और पूंजीवाद से समाजवाद में परिवर्तन के कार्यक्रम के इर्द–गिर्द मज़दूर वर्ग की राजनीतिक एकता का निर्माण करना है।

http://hindi.cgpi.org/22721

गुजरात में पुल गिरने से सैकड़ों लोगों की मौत :

राज्य की आपराधिक लापरवाही

गुजरात के मोरबी शहर में मच्छू नदी से 141 पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के शव निकाले गए हैं। यह पुल 30 अक्तूबर को रविवार की शाम को 6 बजकर 40 मिनट पर, उस समय पर गिर गया जब सैकड़ों लोग नदी पर बने झूला पुल (सस्पेंशन पुल) पर छुट्टी के दिन घूमने आये थे। मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है और कई लोग लापता बताए जा रहे हैं।

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी पुल गिरने से जान गंवाने वाले परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करती है।

सस्पेंशन पुल का गिरना सर्वोच्च पदों पर बैठे अधिकारियों की आपराधिक लापरवाही और पुल के रखरखाव और संचालन के लिए ज़िम्मेदार निजी पूंजीपतियों के साथ उनकी मिलीभगत की ओर इशारा करता है।

150 साल पुराना और 756 मीटर लंबा यह सस्पेंशन पुल उस समय टूट गया जब उस पर 400–500 लोग मौजूद थे, यानी कि इसकी क्षमता से तीन गुना अधिक लोग। पुल के टूटने के जाने से सैकड़ों लोग नदी में जा गिरे।

मोरबी नगर पालिका के अधिकारियों के अनुसार, इस पुल के संचालन और रखरखाव का काम 15 साल के लिए ओरेवा नामक एक निजी कंपनी को दिया गया था। मार्च 2022 में इस पुल का नवीनीकरण करने हेतु जनता के लिए इसे बंद कर दिया गया था। इसे मरम्मत के बाद, 26 अक्टूबर को गुजराती नववर्ष के दिन फिर से खोला गया। लेकिन स्थानीय नगर पालिका ने (नवीकरण के बाद) अभी तक कोई फिटनेस प्रमाण पत्र जारी नहीं किया था।

कुछ ऐसे लोग, जो उस पुल को देखने के लिए गए थे और सौभाग्य से पुल गिरने से पहले ही वापस आ गए थे, उन्होंने बताया कि पुल पर बहुत भीड़भाड़ थी और स्पष्ट तरीक़े से यह नज़र आ रहा था कि उस पर क्षमता से कई गुना अधिक लोग मौजूद थे। लोगों ने पुल पर उसकी क्षमता से ज्यादा लोग होने की और दुर्घटना होने की संभावना के बारे में अधिकारियों को चेतावनी देने की कोशिश भी की थी, लेकिन अधिकारियों ने इन चेतावनियों को नज़र अंदाज कर दिया। पुल का संचालन करने वाली निजी कंपनी ने चेतावनियों के बावजूद अपना राजस्व बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक लोगों के लिये टिकट जारी करती रही।

आसपास रहने वाले लोग तुरंत मौके पर पहुंच गए। उनमें से कई लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर पानी में कूद गए और लोगों को किनारे पर खींच कर लाये, उन्होंने ऐसे लोगों की भी सहायता की जो तैरकर किनारे तक पहुंच सकते थे। स्थानीय मछुआरों ने सबसे पहले अपनी नौकाओं से मदद की। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एन.डी.आर.एफ.), थलसेना, नौसेना और वायुसेना की टीमों को भी बचाव कार्य में लगाया गया था।

इस घटना में इतने लोगों की दुखद मौत के लिए राज्य की आपराधिक लापरवाही ज़िम्मेदार है। जब पुल को कोई फिटनेस प्रमाण पत्र जारी ही नहीं किया गया था, तो राज्य के अधिकारी प्रमाणित क्षमता से कई गुना अधिक लोगों को, सैकड़ों संख्या में पुल पर इकट्ठा होने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? अधिकारियों को लोगों द्वारा दी गई चेतावनी बावजूद भी दुर्घटना को रोकने के लिए कोई क़दम नहीं उठाया गया। सार्वजनिक स्थानों पर, जहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, वहां लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य की ज़िम्मेदारी है। इस संबंध में राज्य द्वारा अपने कर्तव्य को पूरा करने की कमी से, लोगों की मृत्यु होना, हत्या से कम नहीं है।

लोग इस घटना की गहन जांच की मांग कर रहे हैं। वे कई सवालों के जवाब मांग रहे हैं, जिन्हें अधिकारियों द्वारा अब तक अंधेरे में रखा गया है, जैसे कि ठेकेदार ने पुल के नवीनीकरण के लिये कौन–सी सामग्री का उपयोग किया था, फिटनेस प्रमाण पत्र जारी होने से पहले पुल को

शेष पृष्ठ 7 पर

जनसंहार की 38वीं बरसी

पृष्ठ 1 का शेष

"दंगा" कहना, जो कि आधिकारिक प्रवक्ता अभी भी कहते हैं, यह पूरी तरह से झूठ है। वह राज्य द्वारा आयोजित जनसंहार था।

पिछले 38 वर्षों में हमारे लोगों के ख़िलाफ़ बार–बार होने वाली सांप्रदायिक हिंसा और राजकीय आतंकवाद को और तेज़ी से बढ़ाया गया है। जो लोग सांप्रदायिक हिंसा आयोजित करते हैं और हमारी एकता को तोड़ते हैं उन्हें कभी भी सज़ा नहीं मिलती। भाजपा और कांग्रेस पार्टी जैसी राजनीतिक पार्टियां राष्ट्रीय एकता की रक्षा करने की बात करती हैं लेकिन वास्तविकता में लगातार लोगों को बांटने का काम करती हैं। यह सोचना ग़लत है कि सांप्रदायिक हिंसा का स्रोत केवल भाजपा ही है, और इसे सत्ता से हटा देने से समस्या का समाधान हो जाएगा। एस. राघवन ने बताया कि सांप्रदायिक हिंसा और राजकीय आतंक के ख़िलाफ़ संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए हमें अपने अधिकारों को हासिल करने के लिये, सभी शोषित और उत्पीड़ित लोगों के बीच एक मजबूत एकता बनानी होगी और उसे लगातार मजबूत करते रहना होगा।

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के वक्ता, कॉमरेड बिरजू नायक ने विस्तार से बताया कि नवंबर 1984 में जो हुआ, वह राज्य द्वारा आयोजित एक जनसंहार था। पिछले 38 वर्षों में, सत्ता में आने वाली एक के बाद एक, हर पार्टी और गठबंधन के द्वारा सच को छुपाने के लिये किये गये लगातार प्रयासों से यह स्पष्ट होता है कि उस जनसंहार के पीछे शासक वर्ग और उसकी पूरी राज्य मशीनरी का हाथ था। जबकि कांग्रेस पार्टी और उस समय सत्ता के प्रमुख पदों पर बैठे अधिकारी इस जनसंहार को आयोजित करने के लिए ज़िम्मेदार थे, तो वह जनसंहार पूरे शासक वर्ग के पक्ष में किया गया था। शासक वर्ग ने अपने अंतर्विरोधों को हल करने के लिये तथा मज़दूर वर्ग और मेहनतकश जनता की एकता को तोड़ने के लिए उस जनसंहार का आयोजन किया था।

जो लोग इस विचार को बढ़ावा देते हैं कि 1984 का जनसंहार एक विचलन था, वे लोगों को भाजपा के साथ अपनी प्रतिद्वंद्विता में, कांग्रेस पार्टी के पीछे खड़े होने का आह्वान करने की लाइन को सही ठहराने के लिए ऐसा कर रहे हैं। वे इस गलत धारणा को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक हिंसा का स्रोत एक विशेष राजनीतिक पार्टी, भाजपा है, न कि संपूर्ण शासक वर्ग। यह एक ऐसी लाइन है जो सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक हिंसा के ख़िलाफ़ हमारे संघर्ष को गुमराह कर देगी।

यह सोचना गलत है कि साम्प्रदायिक हिंसा का स्रोत केवल एक पार्टी, यानी बीजेपी है, और किसी एक पार्टी जो सत्ता में है उसको बदलने से, समस्या का समाधान हो जाएगा।

सांप्रदायिक हिंसा और राजकीय आतंकवाद का स्रोत इजारेदार घरानों के नेतृत्व वाले पूंजीपति वर्ग के शासन में निहित है। सांप्रदायिक हिंसा और राजकीय आतंकवाद का उद्देश्य हमारे देश के मज़दूर वर्ग और मेहनतकश जनता की फौलादी एकता को तोड़ना और अपने अधिकारों के लिए हमारे संघर्ष को कुचलना है। सांप्रदायिक हिंसा और राजकीय आतंक के ख़िलाफ़ अपने संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए, सभी शोषित और उत्पीड़ित लोगों की, और सभी प्रगतिशील और लोकतांत्रिक ताक़तों की, सभी के अधिकारों की सुरक्षा के लिए, एक राजनीतिक एकता को बनाना और मजबूत करना आवश्यक है। हमारे संघर्ष को एक ऐसे नए राज्य की स्थापना के उद्देश्य से आगे ले जाना है, जो यह सुनिश्चित करेगा कि किसी के साथ उसके विचारों के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, और जो इस तरह के भेदभाव करता है, उसे तुरंत कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी, चाहे वह कोई भी हो और किसी भी पद पर हो।

साम्प्रदायिक हिंसा और राजकीय आतंकवाद का स्रोत इजारेदार घरानों के नेतृत्व वाले पूंजीपति वर्ग के शासन में निहित है। साम्प्रदायिक हिंसा और राजकीय आतंकवाद का लक्ष्य हमारे देश के मज़दूर वर्ग और मेहनतकश जनता की फौलादी एकता को तोड़ना और अपने अधिकारों के लिए हमारे संघर्ष को कुचलना है।

बैठक को संबोधित करने वालों में शामिल थे – जमात–ए–इस्लामी हिंद के इनाम उर रहमान, भाकपा (माले) न्यू प्रोलेतेरियन के कामरेड शिवमंगल सिद्धांतकर, सिख फोरम के लल्ली सिंह साहनी, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के मोहम्मद आरिफ, एडवोकेट शाहिद अली, मज़दूर एकता कमेटी के संतोष कुमार और इंकलाबी मजदूर केंद्र के कॉमरेड मुन्ना प्रसाद।

सभी वक्ताओं ने बताया कि पिछले 38 वर्षों से लगातार सरकारें इस झूठ को दोहराती रही हैं कि नवंबर 1984 में जो हुआ वह एक "सिख विरोधी दंगा" था, यानी इंदिरा गांधी की हत्या की "स्वतःस्फूर्त" प्रतिक्रिया थी। लेकिन हक़ीक़त तो यह है कि हर जगह लोगों ने अपने सिख पड़ोसियों को बचाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने कई अनुभवों को बताते हुए दिखाया कि उस जनसंहार की योजना पहले से ही बनाई गई थी और उस समय केंद्र सरकार की प्रभारी पार्टी – कांग्रेस पार्टी ने उसे अंजाम दिया था। उसे लागू करने के लिए पूरे राज्य–तंत्र ने सक्रिय रूप से काम किया था।

पिछले 38 साल से लोग मांग कर रहे हैं कि सरकार 1984 के जनसंहार के पीछे की सच्चाई का खुलासा करे। लोग मांग कर रहे हैं कि उस जनसंहार को आयोजित करने वाले गुनहगारों को तुरंत कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। हरेक सरकार की प्रतिक्रिया केवल जांच आयोगों का गठन करने तक ही सीमित रही है। और उन सब आयोगों ने जनसंहार को आयोजित करने में, केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय और राज्य के विभिन्न अंगों की भूमिका को छुपाने का काम किया है।

वक्ताओं ने पिछले 38 वर्षों के दौरान राज्य द्वारा आयोजित सांप्रदायिक हिंसा की बार–बार होने वाली घटनाओं का ज़िक्र करते हुए, सुनियोजित तरीक़े से राजकीय आतंकवाद की लगातार वृद्धि पर प्रकाश डाला। 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद सांप्रदायिक आतंक, 2002 में गुजरात में मुसलमानों का नरसंहार और कई अन्य दिल दहलाने वाले हत्याकांडों को सत्ता में बैठी पार्टियों की पूर्ण भागीदारी और राज्य मशीनरी की सक्रिय तैनाती के साथ, आयोजित किया गया है। जो लोग सांप्रदायिक जनसंहार आयोजित करते हैं और हमारे लोगों की एकता पर हमला करते हैं, उन्हें सज़ा नहीं मिलती है बल्कि वे राज्य में सर्वोच्च पदों पर पहुँच जाते हैं। दूसरी ओर, अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाले लोगों को टाडा, पोटा और यू.ए.पी.ए. जैसे फासीवादी क़ानूनों के तहत वर्षों तक कैद में रखा जाता है।

कई वक्ताओं ने भाजपा और कांग्रेस जैसी राजनीतिक पार्टियों की भूमिका पर अपने विचार व्यक्त किये। ये राजनीतिक पार्टियां हमारे लोगों की एकता को तोड़ने के लिए सुनियोजित तरीके से धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र के आधार पर, लोगों की भावनाओं को भड़काते हैं। वक्ताओं ने बताया कि केवल सरकार में पार्टी बदलने से सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक हिंसा समाप्त नहीं होगी।

सभी के अधिकारों की रक्षा के लिए, सभी शोषित और उत्पीड़ित लोगों की राजनीतिक एकता को बनाने और मजबूत करने की आवश्यकता को एक बार फिर दोहराते हुए, बैठक का समापन किया गया।

http://hindi.cgpi.org/22757

पेट्रोलियम निर्यातक देशों द्वारा तेल उत्पादन में कटौती करने के फ़ैसले से अमरीका बौखलाया

पेट्रोलियम निर्यातक राज्यों का 23 सदस्यीय समूह, जिसे ओपेक के नाम से जाना जाता है। इसने तेल के उत्पादन में प्रतिदिन 20 लाख बैरल की कटौती करने के लिए अक्तूबर की शुरुआत में अपनी आपसी सहमति व्यक्त कर दी। यह वर्तमान कटौती दैनिक तेल उत्पादन का लगभग 2 प्रतिशत है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण कच्चे तेल की क़ीमत 83 डॉलर प्रति बैरल से नीचे गिरने की वजह से ओपेक द्वारा लिया गया यह एक क़दम है। इस फ़ैसले ने तुरंत ही वाशिंगटन में ख़तरे की घंटी बजा दी, अमरीकी प्रशासन ने इसे "रूस समर्थक" क़दम बताया है और इसके विरोध में अमरीकी कांग्रेस के सदस्यों ने ओपेक के सदस्यों को सज़ा देने के लिए उपयुक्त क़ानून बनाने की धमकी दी है। अमरीकी साम्राज्यवाद, विशेष रूप से इसलिए नाराज़ है क्योंकि दशकों से सऊदी अरब को अमरीका का अपना ग्राहक राज्य माना जाता रहा है और यह इस समूह का एक प्रमुख सदस्य है।

इस समय अमरीकी साम्राज्यवाद रूस और चीन को अपना मुख्य रणनैतिक प्रतिद्वंद्वी मानता है। अमरीका ने पश्चिमी ताक़तों और नाटो राज्यों के साथ राजनीतिक और सैन्य रूप से रूस को घेरने की कोशिशें कीं, जिसके फलस्वरूप फरवरी के अंत से रूस ने पश्चिमी ताक़तों को पीछे धकलने की गतिविधियां शुरू कर दीं। जिसके बाद, अमरीकी साम्राज्यवाद ने रूस को सज़ा देने के प्रयासों पर ज़ोर लगाया। वह इस लक्ष्य के इर्द–गिर्द, अपने सभी सहयोगियों और अन्य राज्यों को एकजुट करने की कोशिश कर रहा है। इस प्रक्रिया में अमरीकी साम्राज्यवाद यूरोप और पश्चिम एशिया सहित अपने सहयोगियों के हितों की पूरी तरह उपेक्षा कर रहा है।

अमरीकी साम्राज्यवाद रूस के ख़िलाफ़ जिन प्रमुख हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, उनमें से एक प्रमुख हथियार है कि रूस द्वारा किये जाने वाले तेल और गैस के निर्यात पर रोक लगाई जाये, जिससे रूस की आमदनी में भारी कमी आ जाये। अमरीका ने रूसी तेल कंपनियों और उनसे संबंधित अन्य राज्यों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं। जर्मनी जैसे जिन यूरोपीय देशों ने तेल और गैस के लिए रूस के साथ एक मजबूत आर्थिक सांझेदारी बनाई थी, इस दबाव के कारण उन्हें विशेष रूप से नुक़सान हो रहा है। इन महत्वपूर्ण ऊर्जा–आपूर्तियों की बढ़ती क़ीमतों और उन देशों के लोगों पर थोपी गई कठिनाइयों, जिनमें विशेष रूप से आने वाली सर्दियों में होने वाले संकट की वजह से लोगों को होने वाली सब परेशानियों की अमरीका ने पूरी तरह से उपेक्षा की है। यूरोपीय संघ के देशों द्वारा रूसी तेल पर एक पूर्ण तेल प्रतिबंध (पूरी तरह से तेल ख़रीदी पर रोक) दिसंबर में लागू होने की उम्मीद की जा रही है और तेल ख़रीद के लिए एक मूल्य सीमा पर भी सहमति करने की संभावना है।

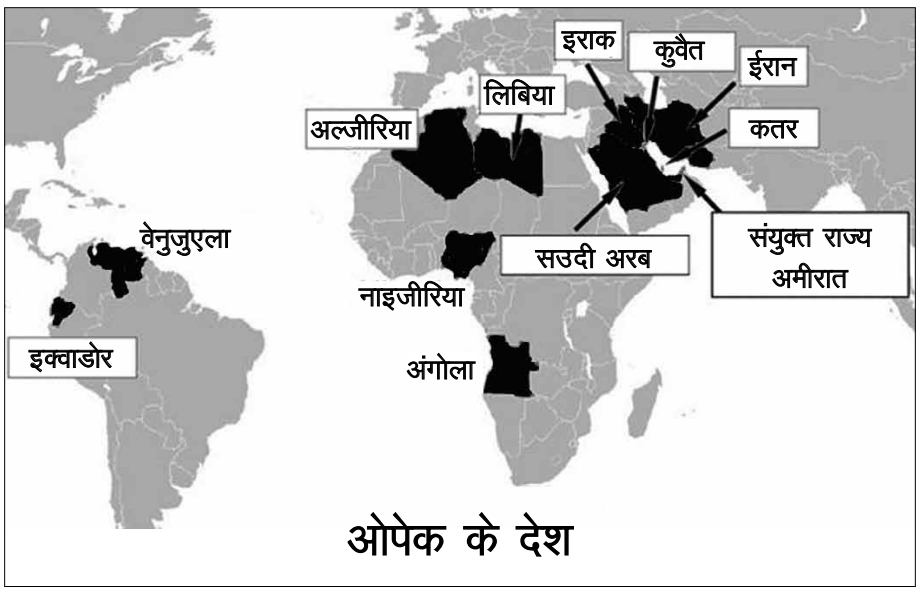

ओपेक के देश

इन सख़्त क़दमों के बावजूद, अमरीकी साम्राज्यवाद रूसी अर्थव्यवस्था को उस तरह से बर्बाद कर पाने में सक्षम नहीं हो सका है जैसी उसने आशा की थी। हक़ीक़त में इस अवधि में हिन्दोस्तान और चीन जैसे देशों ने रूसी तेल की ख़रीद में वृद्धि की है। अन्य देश भी अपने हितों की रक्षा के लिए अमरीका द्वारा लगाये गए प्रतिबंधों के इर्द–गिर्द, उपयुक्त रास्ते तलाश रहे हैं। इस संदर्भ में, हाल ही में ओपेक के तेल उत्पादन में कटौती के फ़ैसले और इस तरह विश्व बाज़ारों में तेल की क़ीमत को बरकरार रखने के निर्णय ने अमरीकी साम्राज्यवाद को झकझोर दिया है।

शुरू में ओपेक को पांच पेट्रोलियम निर्यातक देशों (ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला) द्वारा 1960 में बनाया गया था। उसके बाद के वर्षों में, ओपेक में शामिल होने वाले ऐसे देशों की संख्या बढ़कर 14 हो गई। हाल ही में अजरबैजान, बहरीन, ब्रूनेई, कज़ाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रूस, दक्षिण सूडान और सूडान के शामिल होने के बाद समूह का नाम बदलकर 'ओपेक प्लस' कर दिया गया है। सऊदी अरब और रूस इस समूह के सबसे बड़े निर्यातक हैं।

अमरीका के पास तेल और गैस का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है। यह पिछले दशक में विशेष रूप से शेल तेल के उत्पादन के साथ एक प्रमुख तेल निर्यातक बन गया है। इस प्रकार, सऊदी अरब से उसकी तेल की ख़रीद 20 लाख बैरल से घटकर अब केवल पांच लाख बैरल प्रतिदिन रह गई है। हालांकि, अमरीका ओपेक का सदस्य नहीं है।

पिछले कुछ दशकों से अमरीका ने अपने खुदगर्ज़ आर्थिक और रणनीतिक हितों के अनुरूप, तेल उत्पादन की मात्रा के बारे में ओपेक के निर्णयों में हेरफेर करने के लिए, उसके मुख्य सैन्य आपूर्तिकर्ता के रूप में, सऊदी अरब पर अपनी पकड़ का इस्तेमाल किया है। हालांकि, हाल के वर्षों में सऊदी अरब ने इन मामलों में एक अधिक–स्वतंत्र लाइन का अनुसरण किया है, जबकि यह अभी भी अमरीका के साथ घनिष्ठ राजनीतिक और सैन्य संबंध बनाए हुए है। नतीजतन सऊदी और अमरीकी सरकारों के बीच तनाव बढ़ गया है।

ओपेक राज्यों के ख़िलाफ़, अमरीकी सरकार जिन उपायों को थोपने पर विचार कर रही है, उनमें शामिल हैं : एन.ओ.पी.ई.सी. (नो ऑइल प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्टिंग कार्टेल्स) नामक क़ानून बनाना जो उसे ओपेक पर विश्वास के उल्लंघन (एंटी–ट्रस्ट वोइलेशन) के लिए मुक़दमा करने की अनुमति देगा; इस मामले को विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) के समक्ष लाना; और संयुक्त राज्य अमरीका में ओपेक प्लस सदस्यों की संपत्ति जब्त करना।

अपने वैश्विक–प्रभुत्व को क़ायम रखने के लिए अमरीकी साम्राज्यवाद की मुहिम, दुनिया के लोगों के लिए एक बेहद ख़तरनाक स्थिति पैदा कर रही है। ओपेक के निर्णय से पता चलता है कि अधिक से अधिक देश और लोग अमरीकी हुक्म को मानने से इंकार कर रहे हैं।

http://hindi.cgpi.org/22725

पाठकों की प्रतिक्रिया

1984 में हुये जनसंहार का जीता जागता प्रमाण

संपादक महोदय,

मज़दूर एकता लहर के नवंबर, 1–15 के अंक में प्रकाशित 1984 के जनसंहार के सबक लेख को पढ़कर, मुझे महसूस हुआ कि इसके बारे में और जानकारी लेनी चाहिए।

इसी उद्देश्य से मैं सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी निकालने लगा। उसी दौरान मुझे दिल्ली की एक ऐसी कॉलोनी के बारे में जानकारी मिली, जिसमें 1984 की यादें आज भी उसकी गलियों में छुपी हुई हैं।

यह कालोनी दिल्ली के तिलक नगर इलाके में विधवा (विडो) कॉलोनी के नाम से जानी जाती है।

मैं इस कॉलोनी और 1984 के सिख विरोधी जनसंहार के बारे में जानने के लिए अगले ही दिन में तिलक नगर के लिए रवाना हो गया।

तिलक नगर मेट्रो स्टेशन के पास मुझे सरदार मदन सिंह मिले, वे एक ई–रिक्शा चालक हैं, उन्होंने बताया कि 2 नवम्बर को उनकी चाचा की शादी थी और उसी दिन दंगाइयों ने उनके पिताजी और चाचा को मार दिया और शादी का सारा सामान लूट लिया। तब मदन सिंह 5 साल के थे। उनके परिवार के सदस्य इसीलिये बच पाये क्योंकि उनको मुसलमानों ने मस्जिद में छुपाकर रखा था।

विडो कॉलोनी के हुकम सिंह ने मुझे कई दर्दनाक स्टोरी सुनाई जिसे लिखने की हिम्मत मेरे पास नहीं है। लेकिन उन्होंने बार–बार पूछा हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? दो लोगों की गलतियों की सज़ा पूरी क़ौम को क्यों मिली?

तिलक विहार में गुरुद्वारा शहीदगंज है, जहां 1984 में मारे गए लोगों की तस्वीरें लगाई गई हैं। वहीं भगत सिंह ने बताया कि यह दंगा नहीं था, यह सरकारी क़त्लेआम था।

वे अपनी आप–बीती सुनाते हुए बोले हमारे इलाके को दंगाइयों ने घेर लिया था। हमने घंटों तक संघर्ष किया। दिल्ली पुलिस ने हमें घर जाने को बोला, उनकी बात मानकर अपने घर चले गये। लेकिन कुछ घंटे बाद दंगाइयों ने फिर से हमला कर दिया, हम पुलिस को फोन करते रहे लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।

संपादक महोदय,

इन लोगों कि बातों को सुनकर और आपके लेखक को पढ़कर यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार जिसे 38 सालों से सिख विरोधी दंगा कह रही है, वह राज्य द्वारा आयोजित सिख विरोधी क़त्लेआम था।

दूसरा यह भी स्पष्ट है कि अगर 1984 के गुनहगारों को समय पर सज़ा दी जाती तो उसके बाद होने वाले सांप्रदायिक क़त्लेआम नहीं होते।

1984 का सिख क़त्लेआम हिन्दोस्तान के इतिहास के पन्नों से न तो कभी मिटाया जा सकता है और न ही गुनहगारों को माफ़ किया जा सकता है।

आपका पाठक,
प्रवेश, नई दिल्ली

एक निवेदन

पाठकों से निवेदन है कि मज़दूर, किसान, महिला, नौजवान तथा समाज के हर मेहनतकश श्रेणी की जिंदगी और संघर्ष के बारे में लेख लिखकर भेजें। इससे देश के नव-निर्माण के लिये मज़दूर-मेहनतकशों की राजनीतिक एकता तथा संघर्ष मजबूत होगा।

नौकरियों के बड़े पैमाने पर नष्ट होने का कारण पूंजीवादी लालच है

वर्तमान गहरे आर्थिक संकट की स्थिति में, अपने मुनाफ़ों को और भी बढ़ाने के पूंजीपतियों के प्रयासों की वजह से, दुनियाभर में बड़े पैमाने पर नौकरियों का नाश हो रहा है।

दुनियाभर में प्रौद्योगिकी (आई.टी.) उद्योग में हजारों मज़दूरों ने इस वर्ष अपनी नौकरी खो दी है। एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन सहित अन्य बड़ी आई.टी. कंपनियों द्वारा लगभग 40,000 मज़दूरों को काम से निकाल दिया गया है। इनमें से कई कंपनियों ने अप्रैल–जून 2022 में अपनी आमदनी में गिरावट का अनुभव किया और इसके जवाब में, उन्होंने कई मज़दूरों को नौकरी से निकाल दिया। स्टार्ट–अप कंपनियों में सैकड़ों में छंटनी हो रही है तो विशाल आई.टी. कंपनियों में मज़दूरों की सामूहिक छंटनी हो रही है।

आमतौर पर, आर्थिक मंदी में, कंपनियों में पहले नए मज़दूरों को नौकरी पर लेने पर रोक लगाई जाती है, फिर उनके वेतन में कटौती की जाती है, उसके बाद छंटनी की जाती है। इन क़दमों से आई.टी. उद्योग में काम करने वाले मज़दूर बेहद असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कई उदहारण सामने आये हैं, जिनमें कर्मचारियों को कंपनियों के मानव–संसाधन (एच.आर.) विभागों से वीडियो संदेश प्राप्त हुए हैं, जिनमें उन्हें सूचित किया गया है कि उसी क्षण से कंपनी में उनकी नौकरी ख़त्म है।

ऐसी कंपनियां मान ही नहीं रही हैं कि उन्होंने छंटनी की है। वे इन क़दमों को भ्रामक–शब्दों में छुपाने की कोशिश करती हैं। माइक्रोसॉफ्ट के एक प्रवक्ता ने कहा है कि उनकी कंपनी "सुनिश्चित कर रही है कि सही संसाधन, सही अवसर के साथ जुड़े हुए हैं"। जबकि हक़ीक़त यह है कि कुछ डिवीजनों में मज़दूरों की पूरी टीमों को काम से निकाल दिया गया है।

निवेश–बैंकिंग एक अन्य आर्थिक क्षेत्र है जिसमें मज़दूरों की होने वाली सामूहिक छंटनी के संकेत दिख रहे हैं। कोविड के बाद यह उम्मीद की जा रही थी कि आर्थिक गतिविधियां बढ़ जायेंगी। निवेश–बैंकों ने ट्रेडिंग (शेयर बाज़ार में) और डील–मेकिंग (विलय और अधिग्रहण का प्रबंधन) से उनकी ब्रोकरेज और कमीशन से बनने वाली आमदनी में बड़ी उछाल की आशा की थी। परन्तु, अगस्त 2022 तक, निवेश बैंकों को यह अंदेशा होने लगा था कि दूसरी तिमाही (जुलाई–सितंबर 2022) में पिछले साल के मुक़ाबले में उनकी आमदनी में 30–35 प्रतिशत से अधिक की कमी होगी।

निवेश बैंकों में आमदनी गिरने की स्थिति में, पहली प्रतिक्रिया लोगों को कम वेतन देना होता है। लेकिन अगर आमदनी का स्तर, स्थायी रूप से कम हो जाता है तो उनका अगला क़दम, बैंक कर्मचारियों की छंटनी होता है।

हिन्दोस्तान में एजुकेशन टेक्नोलॉजी (एडटेक) कंपनियों में बड़ी छंटनी देखने को मिली है। वे इस साल जनवरी में शुरू हुई, जब लीडो लर्निंग नाम की कम्पनी ने, कम्पनी को बंद करने की घोषणा की और लगभग 2,000 कर्मचारियों को नयी नौकरियों की तलाश शुरू करने के लिए कहा।

एडटेक कंपनियां, चार साल की उम्र के स्कूली छात्रों से शुरुआत करके, हाई स्कूल तक के छात्रों को प्रतियोगी–परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण देने के लिए, ई–लर्निंग प्रोग्राम बेचती हैं। कोविड–19 महामारी के दौरान ऐसी कंपनियों की संख्या और विस्तार, दोनों में तेज़ी से वृद्धि हुई थी।

अब सभी स्तरों पर, कक्षाओं में नियमित शिक्षण की बहाली के साथ, एडटेक कंपनियों के बीच भयंकर प्रतिस्पर्धा चल रही है। इसके फलस्वरूप, उनकी बिक्री और आमदनी, दोनों में कमी आई है। सबसे बड़ी 10 एडटेक कंपनियों में, अनएकेडमी, वेदांतु और बायजू सहित, कई कंपनियों ने "नियमित–मूल्यांकन प्रक्रिया और पुनर्मूल्यांकन" करने के बहाने, कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर दी है। जून से अब तक, अकेले बायजू ने ही 1,500–2,000 कर्मचारियों की छंटनी की है।

तीन साल पहले, हिन्दोस्तान में एडटेक कंपनियों का, विशेष रूप से युवाओं के लिए, सबसे बड़ी नौकरी देने वाली कंपनियों के रूप में प्रचार किया जाता था। लेकिन आज, वे देश में ज्यादातर युवाओं की छंटनी के लिए सबसे ज्यादा ज़िम्मेदार हैं।

शासक वर्ग के नेता हमारे देश के युवाओं के लिए पर्याप्त रोज़गार पैदा करने के वादे दोहराते रहते हैं। वे इस सच्चाई को छिपाते हैं कि पूंजीवाद, समाज में उपलब्ध श्रम–शक्ति को उत्पादक रूप से नियोजित करने में पूर्णतया असमर्थ है। जैसे–जैसे वित्त–पूंजी अधिकतम मुनाफ़ों की तलाश में एक उद्योग से दूसरे उद्योग में जाती है, वैसे–वैसे वह कई उद्योगों में पूरी तबाही फैलाकर, उन्हें पीछे छोड़ देती है। अर्थव्यवस्था की वे शाखाएं जो किसी एक समय में बहुत सारे रोज़गार पैदा करने वाली शाखाओं के रूप में उभरती हैं, वे मुनाफ़ों की दर में गिरावट आने पर, उन्हीं नौकरियों को ख़त्म करने में सबसे आगे होती हैं। पूंजीवादी व्यवस्था का यह एक अनिवार्य नियम है और यह तब तक जारी रहेगा जब तक समाज में उत्पादन, निवेश और रोज़गार केवल पूंजीवादी लालच को पूरा करने के उद्देश्य से किये जायेंगे, न कि समाज की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये।

http://hindi.cgpi.org/22734

नोटबंदी की छठी वर्षगांठ पर :

नोटबंदी का वास्तविक उद्देश्य स्पष्ट हुआ

छः साल पहले, 8 नवंबर, 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवल चार घंटे के नोटिस पर, सभी 500 और 1000 रुपये के नोटों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी।

प्रधानमंत्री ने दावा किया था कि नोटबंदी से काले धन का पता चलेगा, भ्रष्टाचार ख़त्म होगा और आतंकवाद के लिए मिलने वाले धन पर रोक लगेगी। उन्होंने यह भी दावा किया था कि इससे अमीर और ग़रीब के बीच की असमानता कम हो जायेगी। उन्होंने लोगों से "दीर्घकालिक फ़ायदे" के लिए "कुछ थोड़े समय के" दर्द को बर्दाश्त करने के लिए कहा था।

इनमें से हर एक दावा झूठा साबित हुआ है।

नोटबंदी ने लोगों के लिए एक बहुत ही गंभीर व लंबे समय तक के लिये नकदी का संकट पैदा किया था। इस क़दम ने लोगों को अपनी सारी बचत को बैंकों में जमा करने और नकद भुगतान के बजाय डिजिटल भुगतान प्रणाली को अपनाने के लिए मजबूर किया।

पिछले पांच सालों में, बिना नगद के (कैशलेस डिजिटल) लेनदेन करने की संख्या लगभग पांच गुना बढ़ गई है। 2021–22 में डिजिटल लेनदेन करने की संख्या 7,400 करोड़ से अधिक रही, जिनके ज़रिये 1,000 लाख करोड़ रुपये से अधिक का लेनदेन हुआ है। इसके साथ ही अब हिन्दोस्तान डिजिटल भुगतान में दुनिया का सबसे बड़ा बाज़ार है।

बड़े पैमाने पर डिजिटल भुगतान के उपयोग ने वित्तीय–तकनीकी सेवायें प्रदान करने वाली हिन्दोस्तानी और विदेशी इजारेदार पूंजीवादी कंपनियों को भारी मुनाफ़ा कमाने का मौका दिया है। इनमें गूगल, पेटीएम, फोनपे, एयरटेल और जिओ के पेमेंट बैंक शामिल हैं।

कामकाजी लोगों पर नोटबंदी का असर बेहद विनाशकारी था। अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्र जो बड़े पैमाने पर नगद लेनदेन पर निर्भर हैं, जैसे कि कृषि, थोक और खुदरा व्यापार, निर्माण और पर्यटन, ये सब गंभीर रूप से प्रभावित हुए।

आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए भुगतान न कर पाने के कारण कई मौतों की ख़बरें भी मिली थीं। उनकी उस पीड़ा को "अस्थायी पीड़ा" कहा गया था।

तीन लाख से अधिक छोटे और मध्यम स्तर के औद्योगिक कारोबारों के बंद होने से, लगभग चार करोड़ लोग बेरोज़गार हो गए थे। इनमें से कई कारोबार अपना उत्पादन और सेवाएं फिर से शुरू ही नहीं कर पाये। उनका दर्द अस्थायी नहीं, बल्कि स्थायी था।

इससे केवल पूंजीवादी अरबपतियों के लिए ही "दीर्घकालिक लाभ" सुनिश्चित हुआ है। वास्तव में, उनके हित के लिये ही नोटबंदी की गई थी।

स्वयं प्रधानमंत्री ने 27 नवंबर, 2016 को नोटबंदी के असली उद्देश्य का खुलासा किया था, जब उन्होंने कहा था कि "गैर–नगदी वाला समाज बनाने के सपने को साकार करने के लिये ही देश इस महान कार्य को आज पूरा करना चाहता है।"

नकदी का उपयोग कम करना, भ्रष्टाचार को कम करने के बराबर नहीं है। भ्रष्टाचार कई प्रकार के होते हैं, जिनमें नकदी का इस्तेमाल नहीं होता है। चुनावों के नतीजों को प्रभावित करने के लिए पूंजीवादी कंपनियों द्वारा इलेक्टोरल–बॉन्ड्स का इस्तेमाल ऐसा ही एक उदाहरण है। सरकारी बैंकों के द्वारा पूंजीवादी कंपनियों के न चुकाए गए, भारी कर्ज़ों को माफ़ करवाना, यह सबसे बड़ा भ्रष्टाचार–कांड है, जो हाल के दिनों में हो रहा है। निजीकरण, विनिवेश और मुद्रीकरण के नाम पर, सार्वजनिक संपत्ति को कौड़ियों के दाम पर निजी कंपनियों को बेचना भी भ्रष्टाचार का एक प्रमुख रूप है।

सरकार का एक वादा यह भी था कि इतना काला धन जब्त किया जाएगा कि हर ग़रीब के बैंक खाते में 15 लाख रुपये जमा कराए जाएंगे। स्पष्ट है कि छः साल बाद भी, यह वादा पूरा नहीं किया गया है। विदेशों में जमा काला धन वापस लाने का दावा भी पूरी तरह झूठा साबित हुआ है।

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि उसे नोटबंदी से 4–5 लाख करोड़ रुपये के काले धन की वसूली की उम्मीद है। स्पष्ट है कि यह बयान भी झूठा साबित हुआ। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 30 अगस्त, 2017 को जारी की गई वार्षिक रिपोर्ट से पता चला है कि उस तारीख़ तक 98.96 प्रतिशत पुराने नोट बैंकों में वापस आ गए थे। केवल 16,000 करोड़ रुपये के नोट ही वापस नहीं आये थे।

प्रधानमंत्री का दावा कि नोटबंदी से जाली नोटों का सफाया हो जाएगा और आतंकवादी गतिविधियों में कमी आएगी, वह भी पूरी तरह से झूठा साबित हुआ है। जो लोग आतंकवाद के लिए धन देते हैं, वे हाल की क्रिप्टो–मुद्रा सहित, वैत्तिक लेनदेन के कई आधुनिक माध्यमों का उपयोग करते हैं; वे केवल नकली नोटों पर निर्भर नहीं हैं।

नोटबंदी लागू होने के छः साल बाद, यह बहुत स्पष्ट है कि इसने अमीर और ग़रीब के बीच की खाई को कम नहीं किया है। हक़ीक़त में यह अंतर और अधिक बढ़ गया है।

हमारे जीवन के अनुभव ने नोटबंदी को सही ठहराने के लिए सरकार द्वारा किए गए सभी झूठे दावों का पर्दाफ़ाश कर दिया है। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि नोटबंदी का वास्तविक उद्देश्य था सबसे बड़े हिन्दोस्तानी और विदेशी इजारेदार पूंजीपतियों के मुनाफ़ों को बढ़ाने के लिए डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना।

http://hindi.cgpi.org/22736

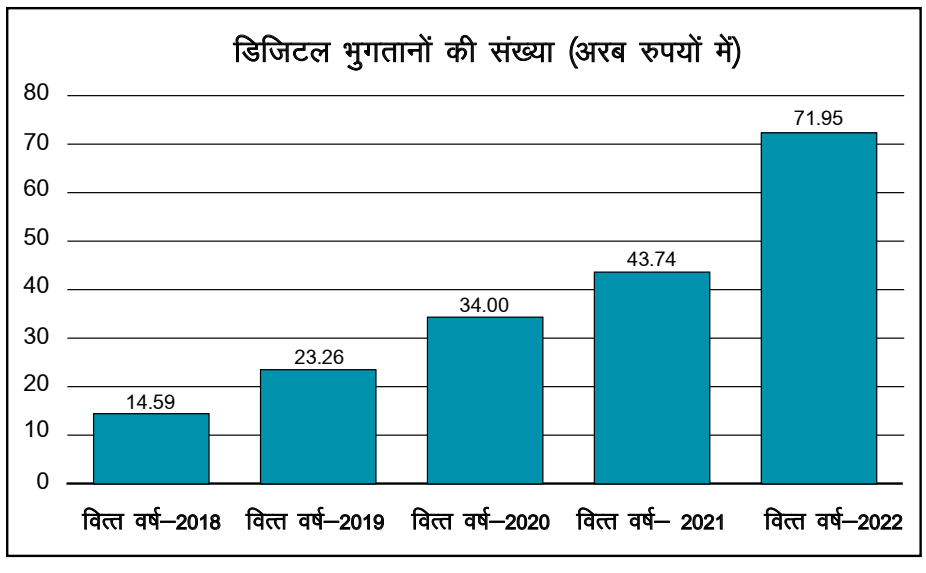

मोटरगाड़ी उद्योग में मज़दूरों का संघर्ष

गुड़गांव–मानेसर क्षेत्र : नियमित मज़दूरों और ठेका मज़दूरों को एकजुट करने का संघर्ष आगे बढ़ रहा है

मोटरगाड़ी और मोटरगाड़ी के पुर्जे बनाने वाले पूरे उद्योग में पूंजीपतियों ने यह सुनिश्चित किया है कि मज़दूरों को स्थाई मज़दूर और ठेके पर काम करने वाले मज़दूर के आधार पर बांट कर रखा जाए। एक समान काम के लिए ठेक पर काम करने वाले मज़दूरों को स्थाई मज़दूरों की तुलना में काफी कम वेतन दिया जाता है। उन्हें सामाजिक सुरक्षा की कोई भी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। पूंजीपति मालिक सरकार के श्रम विभाग के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करते हैं कि ठेका मज़दूरों को यूनियनों में संगठित होने की अनुमति न मिले। न ही उन्हें स्थाई मज़दूरों की यूनियनों में सदस्य के रूप में शामिल होने की अनुमति हो।

स्थाई मज़दूर और साथ ही ठेका मज़दूर, दोनों ही अधिकारों की अपनी लड़ाई के लिए एक संगठन में, एक साथ आकर संघर्ष करने के महत्व को पहचानते हैं। बेलसोनिका ऑटो कंपोनेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मज़दूरों की यूनियन ने ठेका मज़दूरों को सदस्य बनाने के लिये अगस्त 2021 में अपने दरवाज़े खोले। पूरी तरह से यह जानते हुए कि प्रबंधन इस निर्णय को उलटने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, फिर भी यूनियन ने ऐसा क़दम लिया है। सभी मज़दूरों का एक साथ खड़े होना ही सभी मज़दूरों के हित में है इसीलिये यूनियन ने यह तय किया है। उन्होंने पहले क़दम के रूप में ठेके पर काम करने वाले मज़दूरों को अपना सदस्य बनाया।

हरियाणा के लेबर कमिश्नर, जो ट्रेड यूनियनों के रजिस्ट्रार के रूप में भी कार्य करते हैं, उन्होंने प्रबंधन की ओर से यूनियन को एक पत्र भेजकर, यूनियन के द्वारा की गई इस कार्रवाई के लिये 20 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। लेबर कमिश्नर के अनुसार यूनियन का यह क़दम अवैध है। यूनियन ने अपने फ़ैसले की हिफ़ाज़त करते हुए, अपना जवाब लेबर कमिश्नर को भेज दिया है। मज़दूरों को अपनी पसंद की यूनियन बनाने या उसमें शामिल होने के अधिकार की हिफ़ाज़त करते हुये यूनियन ने यह स्पष्टीकरण दिया है कि स्थाई और ठेका मज़दूरों के बीच में कोई भेद नहीं किया जाना चाहिए।

बेलासोनिका के मज़दूरों द्वारा क़ायम की गई यह मिसाल, स्थाई और ठेका मज़दूरों के अधिकारों के उनके संयुक्त संघर्ष को और मजबूत करेगी। उनका यह क़दम मज़दूरों की यूनियनों के बीच एकता को और मजबूत करेगा। तरह–तरह के नियमों और प्रक्रियाओं के ज़रिये मज़दूरों को विभिन्न यूनियनों में बांटकर रखने और एक दूसरे के ख़िलाफ़ उनका इस्तेमाल करने के प्रबंधन के प्रयासों को चुनौती देगा।

मारुति के मज़दूरों ने कंपनी में अपनी बहाली की मांग की

2012 में, मारुति ऑटोमोबाइल्स के मानेसर प्लांट में हुई हिंसा के मद्देनज़र "विश्वास की कमी" का हवाला देते हुए, प्लांट के 546 मज़दूरों को नौकरी से बर्ख़ास्त कर दिया गया था।

बर्ख़ास्त किए गए 546 मज़दूरों में से 426 के ख़िलाफ़ कोई भी आपराधिक आरोप नहीं था। अपने इस दावे को साबित करने के लिए कंपनी द्वारा कोई आंतरिक जांच भी नहीं की गई थी, जिससे यह पता चले कि इन मज़दूरों ने किसी भी तरह का कोई भी ऐसा काम किया हो जो कंपनी के हितों के ख़िलाफ़ था।

बर्ख़ास्त किए गए मज़दूर ने दूसरी अन्य नौकरियों की तलाश करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें दूसरी नौकरी पाने में सफलता नहीं मिली। अपनी नौकरी जाने, घर के लिए किराए का भुगतान न कर पाने और गुड़गांव में अपने लिये दो वक़्त की रोटी का इंतजाम करने में असमर्थ होने के कारण, उनमें से अधिकांश अपने गांवों को लौट गए थे। उनमें से बहुत से मज़दूर, किसानी का काम कर रहे हैं या गांवों में दूसरे अन्य व्यवसायों में ठेके पर काम कर रहे हैं।

फिर भी मज़दूरों ने अपनी रोज़ी–रोटी पर हो रहे अन्यायपूर्ण हमले के ख़िलाफ़ अपनी लड़ाई नहीं छोड़ी है। अपनी नौकरी को बहाल करने की मांग को लेकर, उनमें से सैकड़ों मज़दूरों ने 11–12 अक्तूबर को हरियाणा सरकार के मिनी सचिवालय के बाहर दो दिवसीय भूख हड़ताल में भाग लिया।

जैसा कि सबको याद होगा कि 18 जुलाई, 2012 को मारुति कंपनी के कार्यालय में कंपनी के एक वरिष्ठ प्रबंधक की मौत हो गई थी। यह घटना उस समय हुई थी जब सभी मज़दूर, अन्यायपूर्ण तरीक़े से बर्ख़ास्त किये गए एक मज़दूर को बहाल करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे और मारुति कंपनी के प्रतिनिधियों और मज़दूरों के बीच बातचीत चल रही थी। आग की वजह हुई प्रबंधक की मौत के आरोप सहित, दंगा और आगजनी का आरोप भी मज़दूरों पर लगाया गया था। पूरे गुड़गांव–मानेसर औद्योगिक क्षेत्र में मज़दूरों के बीच आतंक फैलाने के लिए, इस घटना का इस्तेमाल किया गया था। इस माहौल ने न केवल मारुति–सुजुकी में हो रहे संघर्ष को, बल्कि पूरे औद्योगिक क्षेत्र के मज़दूरों द्वारा किये जा रहे अधिकारों के संघर्ष को अत्यधिक क्षति पहुंचाई।

सैकड़ों मज़दूरों को गिरफ़्तार किया गया और उनको महीनों तक प्रताड़ित किया गया। अदालत ने 10 मार्च, 2017 को 148 आरोपियों में से 31 को दोषी ठहराया और बाकी 117 को बरी कर दिया। जबकि ये 117 मज़दूर पहले ही लगभग पांच साल जेल में बिता चुके थे! मारुति–सुजुकी वर्कर्स यूनियन के 12 पदाधिकारियों सहित दोषियों में से 13 को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई।

लंबी अदालती सुनवाई के दौरान, राज्य ने कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया कि मज़दूरों ने कार्यालय में आग लगायी थी, जिसमें प्रबंधक की मौत हो गई। दूसरी ओर अनेक चश्मदीद गवाहों के बयान इस बात की ओर इशारा करते हैं कि आंदोलनकारी मज़दूरों को गेट के बाहर रखा गया था, जबकि प्रबंधन के गुंडे फैक्ट्री परिसर के अंदर थे और जो चाहे करने में सक्षम थे। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि मारुति–सुजुकी के मज़दूरों के शक्तिशाली संघर्ष को कुचलने के लिये और उनकी यूनियन को ख़त्म करने के लिए ही कंपनी द्वारा प्रबंधक की हत्या आयोजित की गई थी।

बर्ख़ास्त किये गये लगभग 340 मज़दूरों ने अपनी अवैध बर्ख़ास्तगी के ख़िलाफ़ 2016 में अदालत की शरण ली थी। लेकिन इस मामले में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है और यह मुक़दमा अब बिना किसी अंत के छह साल से लटका हुआ है। मज़दूरों ने एकजुट होकर अपनी बहाली के लिए दबाव बनाने के अपने आंदोलन को जारी रखने का फ़ैसला किया है। मारुति–सुजुकी के मज़दूरों की बहाली की मांग को गुरुग्राम–मानेसर–बावल मोटरगाड़ी औद्योगिक क्षेत्र के सभी मज़दूरों और ट्रेड यूनियनों का भरपूर समर्थन मिला है।

यामाहा मोटर के मज़दूरों ने कंपनी के प्रबंधन द्वारा उन्हें बांटने की योजना को विफल कर दिया

यामाहा मोटर प्राइवेट लिमिटेड के चेन्नई के कांचीपुरम के संयंत्र के बाहरी हिस्से में 10 दिनों तक चले धरने के बाद, मज़दूरों ने 20 अक्तूबर, 2022 को अपनी हड़ताल वापस ले ली। यूनियन ने ऐसा इसलिये किया क्योंकि प्रबंधन मज़दूरों के साथ बातचीत करने के लिए सहमत हो गया है।

प्रबंधन द्वारा मज़दूरों के बीच उनकी एकता तोड़ने की तमाम कोशिशों के विरोध में, सभी मज़दूर 11 अक्तूबर को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे। मज़दूरों की एकता को तोड़ने के प्रयास में प्रबंधन ने एक फ़र्ज़ी यूनियन बनाई और उस यूनियन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किए।

मज़दूरों की यूनियन पिछले 13 महीनों से प्रबंधन के साथ एक लॉन्ग टाइम सेटलमेंट करने के लिए बातचीत करने की कोशिश कर रही है। प्रबंधन ने यूनियन के साथ बातचीत करने से इंकार कर दिया है। इसकी बजाय, उसने दूसरी यूनियन के साथ बातचीत शुरू की है जिसे स्वयं प्रबंधन ने ही स्थापित किया है।

मज़दूरों की यूनियन से बातचीत करने की उनकी लगातार मांग के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला और आख़िर में उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल का सहारा लिया और प्लांट के अंदर धरना किया। हड़ताल में 500 से अधिक मज़दूरों ने भाग लिया।

हड़ताल को तोड़ने के लिये प्रबंधन द्वारा किये गये विभिन्न प्रयासों – अदालत के ज़रिये प्रतिबंध लगवाने से लेकर, पुलिस की मदद से संघर्ष को कुचलने और संयंत्र को बंद करने की धमकी तक – सभी व्यर्थ साबित हुये। हड़ताली मज़दूरों ने ख़तरे और बारिश का सामना करते हुए, संयंत्र के

शेष पृष्ठ 7 पर

किसानों का संघर्ष जारी है

पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और देश के अन्य भागों के किसान अपनी फ़सलों के लिये लाभकारी दामों पर सुनिश्चित सरकारी ख़रीदी के लिए अपने संघर्ष को जारी रखे हुए हैं। सभी फ़सलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, सभी कृषि की लागतों के लिए राज्य की सब्सिडी, बेहतर सिंचाई सुविधाओं, किसानों की कर्ज़माफ़ी, आदि के लिए और बिजली संशोधन विधेयक के ख़िलाफ़, वे निरंतर संघर्ष में लगे हैं।

इनके साथ ही वे लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्याओं के लिए इंसाफ और आन्दोलनकारी किसानों पर झूठे पुलिस मामलों को वापस लेने की महत्वपूर्ण मांगों के लिए आन्दोलन कर रहे हैं।

किसान यह मांग कर रहे हैं कि सरकार ने दिसम्बर 2021 में किसानों को जो आश्वासन दिए थे, जिसके बाद ही किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर अपना धरना समाप्त किया था, उन आश्वासनों को सरकार पूरा करे।

पंजाब के मुख्यमंत्री का घेराव

9 अक्तूबर, 2022 से भारतीय किसान यूनियन (एकता–उगराहां) की अगुवाई में सैकड़ों किसानों ने 9 अक्तूबर से, संगरूर जिले में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के निवास स्थान पर अनिश्चिकालीन विरोध आंदोलन छेड़ रखा है। किसान अपनी अनेकों मागें उठा रहे हैं, जैसे की बारिश व टिड्डियों तथा अन्य कीड़ों के कारण उनकी फ़सल को जो नुकसान पंहुचा है उसका उन्हें मुआवज़ा मिले; धान की पराली के इंतजाम के लिये प्रत्येक क्विंटल पर 200 रुपये मिले; किसानों की ज़मीन के अधिग्रहण के लिए जायज़ मुआवज़ा मिले; डेयरी पशु पालक किसानों को लंपी चर्म रोग के कारण पशुओं की मृत्यु का उचित मुआवज़ा मिले तथा मकई (मक्का), मूंग दाल और बासमती चावल जैसी फ़सलों के लिए न्यूनतम समर्थक मूल्य मिले।

आन्दोलनकारी किसानों ने अपने ट्रेक्टरों और ट्रालियों को सड़कों के बीचों–बीच खड़ा करके, तीन किलोमीटर तक का रास्ता जाम कर दिया।

भा.कि.यू. (एकता उगराहां) ने राज्य सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर 15 अक्तूबर तक उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो 20 अक्तूबर से मुख्यमंत्री के निवास स्थान का घेराव किया जाएगा। 20 अक्तूबर को पंजाब के अलग–अलग इलाकों से महिलाओं, नौजवानों समेत हजारों किसान घेराव के स्थान पर इकट्ठे हुए। किसान अपने साथ खाने के सामान, गद्दे, रसोई गैस के सिलेंडर, पंखे तथा अन्य ज़रूरी सामान लेकर आए थे। उन्होंने ये सब मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर लम्बे समय तक के घेराव की तैयारी के लिए लाए थे। उन्होंने वहां अस्थाई शरण स्थल भी बनाएं तथा सड़क पर मंच भी बनाये ताकि किसान नेता आन्दोलनकारी किसानों को संबोधित कर सकें। भारतीय किसान यूनियन (एकता उगराहां) के जनरल सेक्रेटरी, सुखदेव सिंह कोकरीकलां ने कहा कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जातीं, तब तक यह आन्दोलन जारी रहेगा।

पंजाब में रेल रोको विरोध

किसान मज़दूर संघर्ष कमेटी पंजाब (के.एम.एस.सी.) ने 3 अक्तूबर को लखीमपुर खीरी में एक साल पहले हुई, पाँच किसानों की हत्या की याद में बहुत ही ज़बरदस्त रेल रोको विरोध आयोजित किया था। पंजाब के हजारों किसानों और खेतीहर मज़दूरों ने दस जिलों में सोलह जगहों पर मुख्य रेल लाइनें बंद कर दीं। मुक्तसर, मानसा, बरनाला, संगरूर, मलेरकोटला, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब और रोपड़, इन आठ जिलों में किसानों ने मुख्यमंत्री के पुतले जलाए और राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा किसानों से किए गए वायदों को पूरा न करने पर उनके ख़िलाफ़ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किए। विरोध की सभी जगहों पर शहीद किसानों की याद व सम्मान में फूल अर्पित किए गये।

किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब के अध्यक्ष सतनाम सिंह पन्नू और सेक्रेटरी सरवन सिंह पंधेर ने इस आंदोलन में किसानों की मुख्य मांगों पर रोशनी डाली।

उनकी मांग थी कि लखीमपुर खीरी में हुयी हत्या के दोषी आशीष मिश्रा को तुरंत पकड़ा जाए और उसे जल्द से जल्द सज़ा दी जाए तथा उसके पिता अजय मिश्रा, जो कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय में राज्य गृहमंत्री हैं, को मंत्री पद से तुरंत हटाया जाए। 2022 का बिजली संसोधन विधेयक एकदम खारिज़ कर दिया जाए। केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार को 23 फ़सलों की ख़रीद की गारंटी का क़ानून बनाना चाहिये। सरकार को किसानों को मुफ़्त पराली के इंतजाम के लिये उपयुक्त सामान देने चाहियें या फिर प्रत्येक एकड़ के लिए 7,000 रुपये देने चाहिएं, वरना किसान अपनी पराली को जलाने को मजबूर होंगे। उन्होंने मांग रखी कि बाढ़ के कारण जो फ़सलें बर्बाद हो गई थीं, उनके लिये प्रत्येक एकड़ पर 50,000 रुपये का मुआवज़ा दिया जाए। इसमें पिछले साल की बासमती और कपास की फसलें भी शामिल हैं।

इससे पहले, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने अपने खेतों के लिए पर्याप्त पानी देने की मांग के साथ, 12 सितम्बर को जबर्दस्त विरोध प्रदर्शन किया था।

संगरूर में मुख्य मंत्री के आवास के सामने किसानों का धरना

आन्दोलनकारी किसानों ने बताया कि भूमिगत जल के स्तर के लगातार गिरते जाने की वजह से पंजाब, जिसमें नदियों का बेशुमार पानी होता था, वह अब एक दशक के अंदर, रेगिस्तान बन गया है। इसका कारण है सरकार द्वारा उन फ़सलों को बढ़ावा देना जिनमें पानी बहुत ज्यादा लगता है। इस समस्या से निपटने के लिए केन्द्र और राज्य सरकार ने कोई क़दम नहीं उठाये, इसलिए किसानों ने उनको दोषी बताया। हजारों किसानों, खेतीहर मज़दूरों, महिलाओं और नौजवानों ने अमृतसर, तरनतारन, गुरदासपुर, होशियारपुर, जलंधर कपूरथला, मोगा, फिरोज़पुर, फाजिल्का, मुक्तसर, फरीदकोट, मानसा, बरनाला, फतेहगढ़ साहिब, पठानकोट और मलेरकोटला जिलों में इन विरोध धरनों में सरगरमी से भाग लिया।

आज़मगढ़ में भूमि अधिग्रहण के ख़िलाफ़ किसानों का आन्दोलन

22 अक्तूबर को उत्तर प्रदेश के आज़मगढ़ में एक हवाई अड्ड के निर्माण के लिए किसानों की भूमि का जबरदस्ती से अधिग्रहण के ख़िलाफ़, किसानों ने 11 दिनों का धरना आयोजित किया। इन धरनों के दौरान किसानों ने खीरिया बाग के हरीराम में लोक संसद आयोजित की, जिनमें हज़ार से ज्यादा किसानों ने बढ़–चढ़कर भाग लिया।

इन विरोध धरनों और प्रदर्शनों में भाग लेने वाले संगठनों में संयुक्त किसान मोर्चा, किसान संग्रामी परिषद, किसान संघर्ष समिति, जय किसान आन्दोलन और भूमिया बचाओ शामिल हैं।

किसानों ने कारपोरेट घरानों के हित में काम करने के लिए, सरकार की कड़ी निंदा की। उन्होंने व्यापारिक उद्देश्य के लिए खेतीहर ज़मीन के अधिग्रहण और खेती के सभी पहलुओं में इजारेदार पूंजीवादी कंपनियों के दबदबे का पुरज़ोर विरोध किया। किसानों ने इस बात की चेतावनी दी कि इस पूंजीवादी दखल व दबदबे से किसान तबाह हो जाएंगे। उन्होंने रेलवे, हवाई अड्डों, फैक्टरियों, अस्पतालों और सभी बड़े उद्योगों और सेवाओं के निजीकरण का घोर विरोध किया, क्योंकि इसमें सरकार लोगों की क़ीमत पर, बड़े कारपोरेट घरानों की सेवा कर रही है।

किसानों ने मज़दूरों की छंटनी, फैक्टरियों में तालाबंदी, बढ़ती बेरोज़गारी और महंगाई के सभी मुद्दों पर मज़दूरों को अपना समर्थन प्रकट किया। उन्होंने लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्याओं की कड़ी निंदा की तथा शपथ ली कि जब तक दोषियों को सज़ा नहीं मिलेगी तब तक वे अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। उन्होंने सरकार को अपना मांगपत्र दिया, जिसमें उन्होंने "अपनी ज़मीन का एक इंच भी न देने" का निश्चय ज़ाहिर किया है।

किसान आंदोलन की दूसरी वर्षगांठ पर जोरदार विरोध कार्यक्रम आयोजित करने का आह्वान

संयुक्त किसान मोर्चा (एस.के.एम.) ने देश के सभी राज्यों के किसानों को आह्वान किया है कि 26 नवम्बर, जो कि अब वापस लिए गए तीन किसान–विरोधी क़ानूनों के ख़िलाफ़ किसान आन्दोलन की दूसरी सालगिरह है, के अवसर पर बहुत ही गर्मजोशी के कार्यक्रम करें। एस.के.एम. ने किसानों को अपने–अपने राज्यों में राजभवन तक प्रदर्शन करने का आह्वान दिया।

देशव्यापी प्रदर्शनों और राज्यपालों को मांग पत्र देने के कार्यक्रम का अंतिम रूप एस.के.एम. की नई दिल्ली में 14 नवंबर की मीटिंग में तय किया जाएगा।

एस.के.एम. ने केन्द्र सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम (फोरेस्ट कनज़रवेशन एक्ट) में बदलाव किए जाने की कड़ी निंदा की है। एस.के.एम. ने यह फ़ैसला भी लिया है कि वे 15 नवम्बर को शहीद बिरसा मुंडा की जन्म की वर्षगांठ पर, जो आदिवासी संगठन अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके साथ अपनी हमदर्दी ज़ाहिर करेंगे।

http://hindi.cgpi.org/22750

मोटरगाड़ी मज़दूरों का संघर्ष

पृष्ठ 6 का शेष

परिसर में चौबीसों घंटे अपना धरना जारी रखा। प्रबंधन ने संयंत्र में काम करने वाले अप्रेंटिस मज़दूरों और अस्थाई मज़दूरों को स्थायी नौकरी देने का वादा करके हड़ताल को विफल करने के प्रयास किये तथा और भी साजिशें रचीं। प्रबंधन का इरादा था कि हक़ीक़त में न सही कम से कम काग़ज पर ही प्रबंधन–समर्थक यूनियन में सदस्यों की संख्या में वृद्धि हो। अस्थायी मज़दूरों को नौकरी देने का वादा करने के अलावा, उन्होंने मज़दूरों को कार्यकारी स्तर पर पदोन्नति देने का भी वादा किया। हालांकि, प्रबंधन द्वारा दिये जा रहे सभी प्रलोभनों को ज्यादातर मज़दूरों ने अस्वीकार कर दिया।

मज़दूरों के दृढ़ संघर्ष ने अंततः प्रबंधन को यूनियन के प्रतिनिधियों से बातचीत करने के लिए सहमत होने पर मजबूर कर दिया।

http://hindi.cgpi.org/22723

राज्य की आपराधिक लापरवाही

पृष्ठ 3 का शेष

जनता के लिए क्यों खोला गया, पुल को इस्तेमाल करने के लिए खोले जाने से पहले क्या वास्तव में निरीक्षण और फिटनेस टेस्ट किए गए थे, इत्यादि।

मोरबी पुल का गिरना एक और मानव निर्मित त्रासदी है। इसे हमारे लोगों पर एक ऐसी व्यवस्था ने थोपा है जिसमें राज्य की चिंता निजी पूंजीपतियों के मुनाफ़े को सुनिश्चित करना है, न कि लोगों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करना।

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी मोरबी पुल ढहने की घटना में सैकड़ों लोगों की मौत में राज्य की आपराधिक लापरवाही की निंदा करती है। हम इस घटना की गहन जांच और इन सैकड़ों लोगों की मौत के दोषी सभी लोगों के ख़िलाफ़ सख़्त से सख़्त कार्रवाई करने की मांग करते हैं, इस बात की परवाह किये बिना कि वे प्रशासन में कितने ऊंचे पद पर हैं।

http://hindi.cgpi.org/22703

मज़दूर एकता लहर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट मज़दूर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अख़बार

RNI No.- 45893/86 Postal Regd. No. DL(S)-01/3177/2021-23

LICENSED TO POST WITHOUT PRE-PAYMENT U (SE)-38/2022-23

Posting Date at DLPSO, 16 & 17 Nov, 2022 Date of publish - 16 Nov, 2022

To .....

.....

.....

.....

.....

.....

स्वामी लोक आवाज़ पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रिब्यूटर्स के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मधुसूदन कस्तूरी की तरफ से, ई–392 संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020, से प्रकाशित। शुभम इंटरप्राइजेज, 260 प्रकाश मोहल्ला, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली 110065 से मुद्रित। संपादक–मधुसूदन कस्तूरी, ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020

email : melpaper@yahoo.com, mazdoorektalehar@gmail.com, Mob. 9810167911

अवितरित होने पर इस पते पर वापस भेजें :

ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020

WhatsApp 9868811998

पूरे यूरोप में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन जारी हैं

यूरोप के कई देशों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन एक बार फिर शुरू हो गए हैं। लोग बैनर लेकर बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे रहे हैं और महंगाई के ख़िलाफ़, रूस पर लगाये गये प्रतिबंधों के ख़िलाफ़ और नाटो के विरोध में नारे लगा रहे हैं। इन देशों के लोग यह मांग कर रहे हैं कि उनकी सरकारें नाटो से बाहर निकल जाएं।

फ्रांस, बेल्जियम, मोल्दोवा, चेक गणराज्य, हंगरी और जर्मनी के शहरों में लोगों ने मार्च किया, जिसमें हजारों ने भाग लिया और रूस पर लगे प्रतिबंधों को ख़त्म करने की मांग की, जिसकी वजह से बहुत से घरों और व्यवसायों के लिए आर्थिक संकट पैदा हो गया है।

मज़दूर कह रहे हैं कि मुद्रास्फीति की भरपाई के लिए वेतन वृद्धि हो, ईंधन की क़ीमतों को कम करने के लिए सरकार के ऊर्जा बाज़ार में हस्तक्षेप करे और रूस के ख़िलाफ़ लगाये गये प्रतिबंधों को समाप्त किया जाये। यूरोपीय देशों द्वारा रूस के ख़िलाफ़ लगाए गए प्रतिबंधों के परिणामस्वरूप ऊर्जा के बिलों में भारी वृद्धि हुई है।

एक महीने के भीतर ही पूरे यूरोप में बड़े पैमाने पर होने वाले विरोध प्रदर्शनों की यह दूसरी लहर है। सितंबर की शुरुआत में दसों हजार लोग, बिजली के बढ़ते बिल और दशकों में सबसे अधिक मुद्रास्फीति का विरोध करने के लिए यूरोपीय शहरों की सड़कों पर आ गए।

यूक्रेन की सुरक्षा के नाम पर उनकी सरकारों द्वारा चलाए जा रहे युद्ध को जारी रखने के रवैये के ख़िलाफ़, यूरोप के देशों के मज़दूर वर्ग और लोगों के बीच जागरुकता और विरोध बढ़ रहे हैं। वे देख रहे हैं कि उनकी सरकारें, आम लोगों के हितों की रक्षा करने के बजाय अमरीका और नाटो के हितों के लिए काम कर रही हैं। इन देशों के लोग उनकी सरकारों द्वारा यूक्रेन को की जा रही हथियारों

की आपूर्ति का विरोध कर रहे हैं। युद्ध को समाप्त करने की मांग बढ़ रही है ताकि आर्थिक उथल–पुथल को कम किया जा सके।

22 अक्तूबर को फ्रांस की राजधानी पेरिस की सड़कों पर नाटो और यूरोपीय संघ के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुये थे। हड़ताली शिक्षकों, रेलवे और स्वास्थ्य कर्मियों ने पेरिस सहित दर्जनों और शहरों में मार्च निकाला, यातायात को रोकने की और सार्वजनिक परिवहन को रोकने की कोशिश की। उन्होंने आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती क़ीमतों को पूरा करने के लिए वेतन में वृद्धि की मांग की।

महंगाई से जूझ रही नर्सें और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी पूछ रहे हैं कि जब सरकार यूक्रेन को सैकड़ों मिलियन यूरो के सैन्य उपकरणों को भेज सकती है तो सरकार हमारा वेतन क्यों नहीं बढ़ा सकती। सभी यूनियनों ने आह्वान किया है कि 10 नवंबर को राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन करेंगे।

28 अक्तूबर को चेक गणराज्य के लोग विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे और यूरोपीय यूनियन और नाटो से अपने देश को अलग करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने नारा लगाया कि "रूस हमारा दुश्मन नहीं है, हमलावर चेक सरकार है!"

29 अक्तूबर को रूस के ख़िलाफ़ लगाये गये प्रतिबंधों को हटाने की मांग को लेकर मोल्दोवा में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। उन्होंने यूरोपीय यूनियन समर्थक, नाटो समर्थक और अमरीका समर्थक रुख़ के लिए अपनी सरकार की निंदा की और इसे बदलने का आह्वान किया। उसी दिन शांति के लिए, प्राग में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। प्राग में हजारों प्रदर्शनकारियों ने सर्दियों से पहले ऊर्जा–संकट को दूर करने के लिए, रूस के साथ बातचीत करने का आह्वान किया। उन्होंने घोषणा की कि वे नाटो के हितों को पूरा करने के लिए, सर्दियों में तकलीफें सहने के लिए बिल्कुल सहमत नहीं होंगे।

उसी दिन हैम्बर्ग में शांति और स्वतंत्रता के लिये प्रदर्शन नामक एक विशाल विरोध–प्रदर्शन भी देखने में आया। लोग, जर्मन सरकार की युद्ध समर्थक और जन–विरोधी नीतियों, जीवन यापन की लागत में असहनीय वृद्धि और नाटो के ख़िलाफ़, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। जर्मनी में गर्मियों की समाप्ति के बाद से हर सप्ताह, विरोध रैलियां देखी जा रही हैं।

30 अक्तूबर को हजारों लोगों ने जर्मनी के ड्रेसडेन की सड़कों पर मार्च निकाला और रूस पर लगे प्रतिबंधों को ख़त्म करने की मांग की। फिर, उसी दिन इटली के लोग नाटो के विरोध में और रूस पर लगे प्रतिबंधों के ख़िलाफ़ रोम की सड़कों पर उतरे।

अमरीकी साम्राज्यवाद के वर्चस्व वाली अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने ऊर्जा की बढ़ती क़ीमतों, नाटो के ख़िलाफ़ और अपनी सरकारों के युद्धोन्माद के विरोध में यूरोप के आम लोगों के विरोध प्रदर्शनों को पूरी तरह से ब्लैक आउट कर दिया है।

http://hindi.cgpi.org/22744

राजस्थान में नकली उर्वरक मामले में जांच और मुआवज़े की मांग

उर्वरकों की कीमतें तेज़ी से बढ़ रही हैं। उदाहरण के लिये पिछले तीन सालों में डाई अमोनियम फोस्फेट (डी.ए.पी.) उर्वरक की कीमतें 20,000 रुपये प्रति मैट्रिक टन से बढ़कर 60,000 रुपये प्रति मैट्रिक टन से भी ऊपर पहुँच गयी हैं (चार्ट देखिये)। एक तरफ उर्वरकों की कीमतें आसमान छू रही हैं और दूसरी तरफ ऊंची कीमतें चुकाने पर भी किसानों को असली उर्वरक नहीं मिल रही हैं।

19 अक्तूबर, 2022 को कृषि विभाग के अधिकारियों को यह सूचना मिली कि हनुमानगढ़ जिले के नोहर कस्बे की दुर्गा कॉलोनी में एक सूनसान जगह पर, एक मकान में देश की नामी कंपनियों के बैगों में सुपर फास्फेट तथा मिट्टी की गोलियां डालकर, डीएपी के नाम से नकली उर्वरक तैयार किया जा रहा है।

कृषि अधिकारी जब वहां तहकीकात करने पहुंचे, तो उन्हें वहां पर बड़ी संख्या में नकली डीएपी के बैग मिले और उन बैगों पर नामी कंपनियों के ब्रांड की नकल की हुई थी, जैसे कि चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, इंडियन पोटाश लिमिटेड (आई.पी.एल.), आदि। उस मकान से सिंगल सुपर फास्फेट व एडिटीव के सैकड़ों बैग

डी.ए.पी. उर्वरक की कीमत (रूपये प्रति मैट्रिक टन)

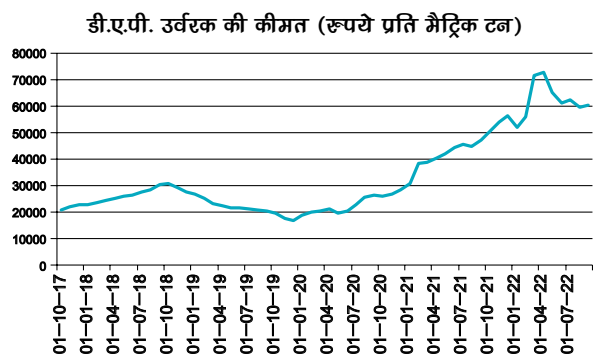

पाए गए। साथ ही, अनेक ऐसे उपकरण भी मिले जिनकी मदद से नकली उर्वरक तैयार किया जा रहा था, जैसे कि इलेक्ट्रिक कांटा, पावर स्प्रेयर, बिल बुक, रजिस्टर, मोबाइल आदि।

लोक राज संगठन के सर्व हिंद उपाध्यक्ष, श्री हनुमान प्रसाद शर्मा की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने 20 अक्तूबर को राजस्थान के नोहर में, नायब तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें नकली खाद बनाने वालों को सज़ा दिलाने की मांग की गयी है। लोक राज संगठन के कार्यकर्ता ताराचंद स्वामी, कृष्ण नोखवाल आदि प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे।

मुख्यमंत्री के नाम से दिये गये इस ज्ञापन में कहा गया है कि अपराधियों को शीघ्र जेल में डालकर, मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, जिससे किसान और किसानी को बचाया जा सके। अभी तक कितना नकली उर्वरक किसानों में बिक चुका है, इसकी जांच करके किसानों को जानकारी दी जाए, ताकि सरकार किसानों की बर्बाद हुई फ़सलों का मुआवज़ा समय पर देकर, किसानों को हुए नुक़सान की भरपाई कर सके।

आंदोलनकारियों ने ऐलान किया है कि अगर अपराधियों को फौरन गिरफ़्तार करके सज़ा न दी गयी और इस मामले में अगर अधिकारी तुरंत जांच करके किसानों को जानकारी नहीं देते, तो लोक राज संगठन सभी किसान संगठनों के साथ एकजुट होकर आंदोलन करेगा।

समस्या की जड़ है कि हिन्दोस्तानी राज्य ने किसानों के लिये उचित दाम पर अच्छी गुणवत्ता की लागत वस्तुओं को उपलब्ध कराने की अपनी ज़िम्मेदारी त्याग दी है। राज्य बढ़ते तौर पर निजी कंपनियों को छूट दे रहा है कि वे किसानों के लिये बीज व उर्वरक जैसी ज़रूरी लागत वस्तुओं को मनमाने दामों पर बेच कर अपने मुनाफ़ों को अधिकतम बनाये। इस परिस्थिति में नकली उर्वरक के बाज़ार को बढ़ावा मिल रहा है, जिसकी वजह से किसानों की परिस्थिति बद से बदतर हो रही है। मज़दूर एकता लहर लोक राज संगठन द्वारा उठायी किसानों की मांगों को जायज़ मानता है और उनका समर्थन करता है।

http://hindi.cgpi.org/22752

मज़दूर एकता लहर का वार्षिक शुल्क और अन्य प्रकाशनों का भुगतान आप बैंक खाते और पेटीएम में भेज सकते हैं

आप वार्षिक ग्राहकी शुल्क (150 रुपये) सीधे हमारे बैंक खाते में या पेटीएम क्यूआर कोड स्केन करके भेजें और भेजने की सूचना नीचे दिये फोन या वाट्सएप पर अवश्य दें।

खाता नाम–लोक आवाज़ पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रिब्यूटर्स

बैंक ऑफ महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली, कालका जी

खाता संख्या–20066800626, **ब्रांच नं.**–00974

IFSCode: MAHB0000974, मो.–9810167911

वाट्सएप और पेटीएम नं.-9868811998

email: mazdoorektalehar@gmail.com